गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 237
दि. 28.12.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

ग्रामीण रोजगार के अधिकार की जंग: मनरेगा को लेकर कांग्रेस का राष्ट्रव्यापी आंदोलन

(जीएनएस)। देश की राजनीति में एक बार फिर मनरेगा को लेकर बड़ा टकराव सामने आ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को कमजोर करने और अंततः खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। इसी के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देशभर में "मनरेगा बचाओ अभियान" शुरू करने का एलान किया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक योजना का सवाल नहीं है, बल्कि करोड़ों गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण भारत के सम्मान और अधिकार की लड़ाई है, जिसे कांग्रेस सड़क से संसद तक लड़ेगी।

कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि मनरेगा कोई साधारण सरकारी योजना नहीं, बल्कि संविधान की भावना से निकला हुआ वह कानून है जिसने गरीबों को काम का अधिकार दिया। उनके अनुसार, मनरेगा ने गांव के सबसे कमजोर वर्ग को यह भरोसा दिया कि कठिन समय में भी उन्हें रोजगार मिलेगा और पलायन की मजबूरी नहीं झेलनी पड़ेगी। खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना किसी व्यापक अध्ययन, राज्यों से चर्चा या राजनीतिक दलों से संवाद किए इस कानून को कमजोर करने का फैसला किया है, जो सीधे तौर पर गरीब विरोधी कदम है। उन्होंने कहा कि जिस तरह तीन कृषि कानूनों को लेकर देशभर में आंदोलन हुआ और अंततः सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा, उसी तरह मनरेगा को लेकर भी जनता की आवाज उठेगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा।

खरगे ने यह भी कहा कि देश इस समय ऐसे दौर से गुजर रहा है, जब लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों पर गंभीर खतरे मंडरा रहे हैं। उनके मुताबिक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया भी इसी साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के नाम सूची से हटाए जाने का खतरा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बूथ स्तर तक सक्रिय हों, घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी गरीब या वंचित मतदाता का नाम न हटे। खरगे ने साफ कहा कि मनरेगा को बचाने की लड़ाई केवल रोजगार की नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने याद दिलाया कि मनरेगा यूपीए सरकार का एक दूरदर्शी कानून था, जिसकी सराहना न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में हुई। इसी वजह से इस योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया, क्योंकि यह उनके श्रम, स्वावलंबन और गरिमा के विचारों को जमीन पर उतारने वाला कानून था। खरगे ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करना महात्मा गांधी के विचारों और उनके सम्मान पर भी चोट है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पहले भी बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वह नोटबंदी हो या कृषि कानून, और अब उसी रास्ते पर चलते हुए मनरेगा को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और लोकतांत्रिक तरीके से देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा।

राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा को खत्म या कमजोर करना केवल गरीबों पर ही नहीं, बल्कि देश के संघीय ढांचे पर भी सीधा हमला है। राहुल गांधी के अनुसार, मनरेगा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, लोगों को अपने गांव में रहकर सम्मानजनक काम करने का अवसर दिया और संकट के समय लाखों परिवारों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। उन्होंने कहा कि यह योजना विकास का एक ऐसा ढांचा थी, जिसने नीचे से ऊपर तक अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला बिना मंत्रिमंडल से सलाह और बिना किसी गहन अध्ययन के एकतरफा तरीके से लिया, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है।

राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह नोटबंदी का फैसला अचानक लिया गया और उसके गंभीर नतीजे देश ने झेले, उसी तरह मनरेगा को लेकर लिया गया यह कदम भी गरीबों और राज्यों के लिए घातक साबित होगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा और संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष किया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मनरेगा केवल रोजगार देने की योजना नहीं थी, बल्कि यह ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम थी, जिसे कमजोर करना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

वहीं, कांग्रेस के इन आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के बयान को गलत बताते हुए कहा कि मनरेगा के ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनके अनुसार, सरकार ने 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, जिससे योजना और मजबूत होगी। मांझी ने कहा कि मनरेगा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित है और सरकार भी उन्हीं आदर्शों के अनुरूप इसे बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक बताया और कहा कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है।

मोबाइल निर्माण में भारत की वैश्विक छलांग, 'मेक इन इंडिया' से बदली देश की औद्योगिक तस्वीर

(जीएनएस)। पिछले एक दशक में भारत ने जिस तरह से अपने औद्योगिक ढांचे को नए सिरे से गढ़ा है, उसकी सबसे सशक्त मिसाल मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देखने को मिलती है। कभी मोबाइल फोन के आयात पर निर्भर रहने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि नीति, निवेश, रोजगार और आत्मनिर्भरता की उस यात्रा का परिणाम है, जिसने भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में एक निर्णायक भूमिका में खड़ा कर दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, बीते 11 वर्षों में देश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात आठ गुना बढ़ा है और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में छह गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बदलाव की नींव केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' सोच और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई जैसी योजनाओं

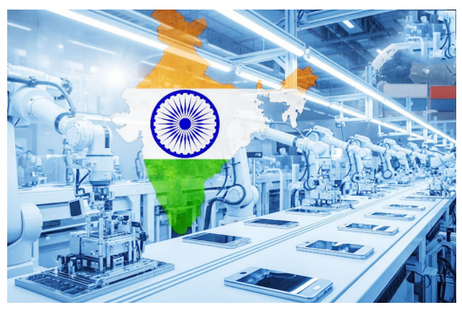

से पड़ी। इन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ कारखाने लगवाना नहीं था, बल्कि भारत को वैश्विक विनिर्माण मानचित्र पर एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में स्थापित करना था। मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में इसका असर सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। आज भारत में बनने वाले स्मार्टफोन न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में निर्यात भी किए जा रहे हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी बन चुकी है।

पीएलआई योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अब तक 13,475 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 9.8 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ है। यह आंकड़ा बताता है कि सरकारी प्रोत्साहन और निजी क्षेत्र की भागीदारी मिलकर किस तरह बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधि को जन्म दे सकती है। इस उत्पादन का सीधा लाभ रोजगार के रूप में भी सामने आया है। बीते पांच वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 1.3 लाख से अधिक नई नौकरियां पैदा हुई हैं, जबकि पिछले दशक में यह संख्या करीब 25 लाख तक पहुंच चुकी है। ये नौकरियां केवल महानगरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के कई छोटे शहरों और औद्योगिक क्लस्टरों में भी फैली हैं, जिससे क्षेत्रीय विकास को भी गति मिली है।

मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी कदम तेज कर दिए हैं, जिसे किसी भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम की रीढ़ माना जाता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दस इकाइयों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें से तीन पहले ही पायलट या शुरुआती उत्पादन के चरण में पहुंच चुकी हैं। यह प्रगति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी ने हाल के वर्षों में वैश्विक उद्योगों को गंभीर संकट में डाला था। भारत का लक्ष्य अब केवल असेंबली तक सीमित रहने का नहीं, बल्कि डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी वैल्यू चेन में आत्मनिर्भर बनने का है।

फ्रंटियर हाईवे परियोजना में पारदर्शिता की कवायद, लाडा–सरली खंड की जमीन और मुआवजे की होगी दोबारा जमीनी जांच

(जीएनएस)। ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ईस्ट कामेंग जिले में प्रस्तावित फ्रंटियर हाईवे परियोजना के लाडा–सरली खंड से जुड़े भूमि स्वामित्व और मुआवजा दावों को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने इस पूरे खंड में जमीन और संपत्तियों की दोबारा जमीनी जांच के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय उस तथ्य-जांच रिपोर्ट के बाद लिया गया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले थे। राज्य सरकार का स्पष्ट कहना है कि किसी भी विकास परियोजना में पारदर्शिता और न्याय सर्वोपरि है, और यदि कहीं भी नियमों की अनदेखी हुई है तो उसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी।

फ्रंटियर हाईवे परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लिए रणनीतिक और विकासात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह परियोजना न केवल सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली है, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और सुरक्षा से जुड़े कई पहलुओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है। ऐसे में इस परियोजना से जुड़ा भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण निष्पक्ष और नियमों के अनुसार होना सरकार की प्राथमिकता है। हाल के महीनों में सामने आई शिकायतों और रिपोर्टों ने इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए पुनः सत्यापन का फैसला लिया। भूमि प्रबंधन विभाग के अनुसार, फ्रंटियर हाईवे परियोजना के लाडा–सरली खंड में शामिल पैकेज-एक से पैकेज-पांच तक की भूमि और संपत्तियों की दोबारा भौतिक जांच कराई जाएगी। इसके लिए नई सत्यापन समितियों का गठन किया गया है, जो सीधे तौर पर जमीन पर जाकर प्रत्येक भूमि खंड की स्थिति, स्वामित्व और वास्तविक उपयोग की जांच करेंगी। इन समितियों की निगरानी ईस्ट कामेंग जिले के उपायुक्त करेंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया पर प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे और किसी भी स्तर पर लापरवाही या पक्षपात की गुंजाइश न रहे।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सत्यापन समितियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्हें स्वीकृत राइट ऑफ वे और स्ट्रिप प्लान के आधार पर जमीन की जांच करनी होगी। इसका अर्थ यह है कि जिस क्षेत्र को परियोजना के लिए अधिग्रहित किया जाना है, उसकी वास्तविक सीमा, उपयोग और दस्तावेजी स्थिति का मिलान किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि जिन लोगों को मुआवजा दिया गया है या जिनके दावे स्वीकृत किए गए हैं, वे वास्तव में उस भूमि या संपत्ति के वैध हकदार हैं या नहीं।

जांच पूरी होने के बाद इन नई समितियों के निष्कर्षों की तुलना पहले गठित समिति द्वारा तय किए गए मुआवजा पुरस्कारों से की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पहले की समिति की अध्यक्षता तत्कालीन उपायुक्त ने की थी और उसी के आधार पर मुआवजा राशि तय की गई थी। अब सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कहीं भी फर्जी दावे, बढ़ा-चढ़ाकर आकलन या नियमों के उल्लंघन के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। यदि जांच में किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह कदम केवल किसी एक परियोजना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संदेश भी है कि विकास के नाम पर किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश जैसे सीमावर्ती और संवेदनशील राज्य में बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके साथ जुड़े सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जमीन देने वाले स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें उचित मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं फर्जी दावों के जरिए लाभ उठाने वालों पर सख्ती करना भी उतना ही जरूरी है। लाडा–सरली खंड के आसपास के इलाकों में इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। कई स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष तरीके से होती है, तो इससे वास्तविक हकदारों को न्याय मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही शंकाओं का समाधान होगा।

जलवायु का कहर और मानवता की कीमत 2025 में दुनिया ने चुकाई तबाही की भारी

(जीएनएस)। साल 2025 दुनिया के लिए केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं रहा, बल्कि यह प्रकृति और मानव के बीच बिगड़ते संतुलन की एक भयावह चेतावनी बनकर सामने आया। जंगल की आग, भीषण हीटवेव, विनाशकारी बाढ़ और ताकतवर चक्रवाती तूफानों ने मिलकर पूरी दुनिया को झकझोर दिया। इन आपदाओं ने न सिर्फ करोड़ों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त किया, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी गहरा घाव छोड़ा। अंतरराष्ट्रीय संस्था क्रिश्चियन एड की रिपोर्ट 'काउंटिंग द कॉस्ट 2025' के मुताबिक, वर्ष 2025 में चरम मौसम की घटनाओं से दुनिया को 122 बिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा केवल पैसों की क्षति नहीं दर्शाता, बल्कि इसके पीछे छिपी मानवीय पीड़ा, मौतें, विस्थापन और टूटते सपनों की कहानी इससे कहीं अधिक दर्दनाक है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जून से सितंबर के बीच भारत और पाकिस्तान के बड़े हिस्सों में हुई अत्यधिक मानसूनी बारिश को साल की दस सबसे महंगी और सबसे ज्यादा असर डालने वाली जलवायु आपदाओं में शामिल किया गया है। इन दोनों देशों में आई बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाओं में कम से कम 1,860 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 5.6 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। दिलचस्प और चिंताजनक बात यह है कि वित्तीय नुकसान के मामले में यह क्षेत्र दुनिया में पांचवें स्थान पर रहा, लेकिन मौतों की संख्या के लिहाज से यह सबसे ऊपर रहा। यह अंतर साफ दिखाता है कि गरीब और विकासशील देशों में आपदाएं जानलेवा ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहां बचाव, बीमा और पुनर्वास की सुविधाएं बेहद सीमित हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा। क्रिश्चियन एड की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में विशेष रूप से कैलिफोर्निया में लगी भीषण जंगल की आग ने लगभग 60 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया, जो वैश्विक स्तर पर कुल नुकसान का लगभग आधा है। इस एक ही घटना में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। अमेरिका, जो ऐतिहासिक रूप से दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश रहा है, खुद जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों का सबसे बड़ा आर्थिक बोझ झेलता दिखा। रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि ये आंकड़े ज्यादातर बीमाकृत नुकसान पर आधारित हैं, यानी वास्तविक नुकसान इससे कहीं अधिक हो सकता है, क्योंकि कई संपत्तियां और आजीविकाएं बीमा के दायरे में आती ही नहीं। अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर नवंबर महीने में दक्षिण-पूर्व एशिया में आए साइक्लोन और बाढ़ की घटनाएं रहीं। इन आपदाओं से करीब 25 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम और मलेशिया जैसे देशों में 1,750 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इन देशों में लाखों लोग विस्थापित हुए, खेती तबाह हो गई और बुनियादी ढांचा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ। कई इलाकों में लोग आज भी सामान्य जीवन में लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तीसरे स्थान पर चीन में आई विनाशकारी बाढ़ रही, जिसने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। इस आपदा में कम से कम 30 लोगों की जान गई और करीब 11.7 बिलियन डॉलर का नुकसान दर्ज किया गया। चीन जैसे विशाल और संसाधन-संपन्न देश में भी जलवायु आपदाओं का असर यह दिखाता है कि कोई भी देश खुद को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मान सकता। जलवायु विशेषज्ञों ने इन घटनाओं को केवल प्राकृतिक आपदाएं मानने से इनकार किया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की एटमॉस्फेरिक फिजिक्स की एमेरिटस प्रोफेसर जोआना हेग ने साफ शब्दों में कहा कि ये आपदाएं 'कुदरती' नहीं हैं, बल्कि लगातार फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल, बढ़ते कार्बन उत्सर्जन और राजनीतिक स्तर पर की गई देरी का नतीजा हैं।

छत्तीसगढ़ शराब मामले में जांच का बड़ा मोड़, ईडी ने दायर की अंतिम अभियोजन शिकायत, 81 आरोपियों तक पहुंचा दायरा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की जांच अब एक निर्णायक चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने इस बहुचर्चित धनशोधन मामले में शुक्रवार को अंतिम अभियोजन शिकायत अदालत में दायर कर दी है। इस शिकायत के साथ ही जांच का वह हिस्सा पूरा माना जा रहा है, जिसमें लंबे समय से संदिग्ध लेन-देन, कथित भ्रष्टाचार और संगठित आर्थिक अपराध की परतें खुलती रही हैं। इस अंतिम अभियोजन शिकायत में 59 लोगों को नामजद किया गया है, जिसके बाद इस पूरे मामले में आरोपी बनाए गए लोगों की कुल संख्या 81 तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा अपने आप में इस कथित घोटाले के फैलाव और गंभीरता की ओर इशारा करता है। ईडी की ओर से अदालत में पेश हुए वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में यह अंतिम अभियोजन शिकायत पीएमएलए (धनशोधन निवारण अधिनियम) की विशेष अदालत में दायर की गई है। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि इससे पहले इस मामले में 22 लोगों को आरोपी बनाया जा चुका था, जिनमें से कई को जांच के दौरान गिरफ्तार भी किया गया था। अब जिन 59 लोगों के खिलाफ अंतिम शिकायत दाखिल की गई है, उनके विरुद्ध जांच पूरी हो चुकी है और एजेंसी का मानना है कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

यह मामला छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार से जुड़े कथित घोटाले से संबंधित है, जिसमें सरकारी तंत्र, निजी कारोबारी और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की कथित मिलीभगत के आरोप सामने आते रहे हैं। ईडी की जांच के अनुसार, इस कथित घोटाले के जरिए शराब के कारोबार में बड़े पैमाने पर अवैध कमाई की गई और उस धन को विभिन्न माध्यमों से ठिकाने लगाया गया। जांच एजेंसी का दावा रहा है कि शराब नीति और वितरण प्रणाली का दुरुपयोग कर एक संगठित नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध कमाई की गई, जिसे बाद में धनशोधन के जरिए वैध दिखाने की कोशिश की गई। ईडी ने अपनी जांच के दौरान कई स्थानों पर छापेमारी की, दस्तावेज जब्त किए, डिजिटल साक्ष्य एकत्र किए और दर्जनों लोगों से पूछताछ की। इस प्रक्रिया में सामने आए तथ्यों के आधार पर एजेंसी ने पहले चरण में 22 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की थी। उन आरोपियों में कथित रूप से इस पूरे नेटवर्क के मुख्य सूत्रधार, कारोबारी और कुछ ऐसे लोग शामिल बताए गए, जिन पर अवैध लेन-देन को अंजाम देने और उसे छिपाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। अब अंतिम अभियोजन शिकायत में जिन 59 नए आरोपियों को जोड़ा गया है, उनमें भी कथित रूप से इस नेटवर्क से जुड़े विभिन्न स्तरों के लोग शामिल बताए जा रहे हैं।

इस मामले की कानूनी प्रक्रिया को लेकर यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर ईडी की जांच और अभियोजन से जुड़े कुछ निर्देश दिए थे, जिनका पालन करते हुए एजेंसी ने अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाई। अंतिम अभियोजन शिकायत दायर किया जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि जांच एजेंसी अब अदालत में मामले को ठोस रूप से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इसके बाद अदालत द्वारा आरोप तय करने, सुनवाई शुरू करने और गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। राजनीतिक दृष्टि से भी यह मामला काफी संवेदनशील माना जा रहा है।

संपादकीय

न्याय-अन्याय के बीच

उन्नाव दुराचार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दिए जाने के खिलाफ शुक्रवार को पीड़िता की मां समेत कई लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। वे दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुचर्चित उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत दे दी थी। जिसके बाद फैसले को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं। पीड़िता की मां इस जमानत को रद्द करने और शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कहती रही हैं। वे अपने पति के हत्यारों को फांसी देने की गुहार लगाती नजर आईं। विपक्षी नेता भी आरोप लगाते रहे हैं जिस तरह तकनीकी आधार पर दोषी को छूट दी गई है, उसमें न्यायिक प्रणाली के लिये गलत परंपरा विकसित होगी। जिससे पीड़िता के परिवार का ही नहीं, बल्कि देश की महिलाओं का भरोसा भी टूटेगा। दरअसल, वर्ष 2017 में हुए इस बहुचर्चित मामले में पूर्व विधायक को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी गई थी। जिसे हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पिछले दिनों जमानत दे दी। जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष और कतिपय महिला संगठन मुखर हुए हैं। बल्कि इस मामले की सर्वाइवर का कहना था कि यदि दोषी व्यक्ति जेल से बाहर होगा तो सुरक्षा के लिये मुझे जेल भेज दिया जाए। उल्लेखनीय है कि सजा मिलने के छह साल बाद हाईकोर्ट की एक बैंच ने उसकी सजा निलंबित कर दी थी। पूर्व विधायक को 15 लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के तीन जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया था। सजा निलंबित होने के कुछ ही घंटों के बाद पीड़िता व कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दोषी को जमानत दी गई है। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि दोषी व्यक्ति जेल से बाहर रहेगा तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस मामले में विपक्षी राजनीतिक दलों की भी तल्ख प्रतिक्रियाएं आई हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता ने इस जमानत को निराशाजनक बताया। उल्लेखनीय है कि इस अपराध के सामने आने में दस माह लगे थे। मामले के तूल पकड़ने पर पीड़िता के पिता पर हमला हुआ था। उन्हें बाद में जेल भेज दिया गया था और पुलिस हिरासत में रहस्यमय ढंग से उनकी मृत्यु हो गई थी। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि जमानत की अवधि में सेंगर सर्वाइवर के पांच किमी के दायरे में नहीं आएंगे और दिल्ली में ही रहेंगे। उसे हर सोमवार पुलिस के समक्ष रिपोर्ट करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी कि किसी भी शर्त के उल्लंघन में जमानत रद्द कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि सेंगर ने ट्रायल कोर्ट में दुराचार के लिये दोषी ठहराने वाले फैसले को चुनौती दी थी। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था, उसके खिलाफ बलात्कार, अपहरण और आपराधिक धमकी के आरोप लगे। साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े चार मामलों की सुनवाई दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। इस बीच रायबरेली जाते समय पीड़िता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिसमें उनकी दो मौसियों की मौत हो गई थी। यही वजह है कि ट्रायल कोर्ट ने दुराचार के मामले में सेंगर को दोषी ठहराते हुए न केवल आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी बल्कि निर्देश दिया था कि सीबीआई सर्वाइवर और उसके परिवार के जीवन व स्वतंत्रता की सुरक्षा भी सुनिश्चित करे। इतना ही नहीं ट्रायल कोर्ट ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेंगर के सार्वजनिक सेवक होने के बावजूद अपराध करने को अनैतिक बताया था। जो जनता का विश्वास तोड़ने वाला है। वहीं कानून के जानकार मानते हैं कि पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में भी सेंगर को दस साल की सजा हुई थी, अतः अभी उसके जेल से बाहर आने की संभावना नहीं है। लेकिन इस जमानत के फैसले ने न्याय व अन्याय के सवाल को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा किया है।

अहंकार की राजनीति और लचर नेतृत्व ने इंडिया गठबंधन को 2025 में बिखेर कर रख दिया

> महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के दौरान कांग्रेस ने एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। यह फैसला उस समय और भी चौंकाने वाला था, जब भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई की बात बार-बार दोहराई जा रही थी।

साल 2025 भारतीय राजनीति में विपक्षी गठबंधन इंडिया (I.N.D.I.A.) के लिए आंतरिक टकराव, रणनीतिक भ्रम और नेतृत्व संकट का वर्ष बनकर उभरा। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद जिस गठबंधन से यह अपेक्षा की जा रही थी कि वह एक सशक्त, वैकल्पिक राजनीतिक धारा के रूप में उभरेगा, वही 2025 में अपनी ही कमजोरियों से जूझता नजर आया। यह वर्ष विपक्ष के लिए न तो संगठनात्मक मजबूती लेकर आया, न ही वैचारिक स्पष्टता। सबसे बड़ा और प्रतीकात्मक तथ्य यह रहा कि पूरे 2025 में इंडिया गठबंधन की एक भी औपचारिक बैठक नहीं हुई। किसी भी राजनीतिक गठबंधन के लिए बैठकें केवल औपचारिकता नहीं होतीं, बल्कि संवाद, समन्वय और साझा रणनीति का आधार होती हैं। बैठकों का न होना यह संकेत देता है कि गठबंधन नाम मात्र का रह गया है, जबकि ज़मीनी स्तर पर दल अपनी-अपनी राह चलने लगे हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनावों में यह बिखराव खुलकर सामने आया, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन तोड़कर अलग-अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2024 में लोकसभा चुनावों में सीमित तालमेल के बाद यह उम्मीद थी कि दिल्ली में विपक्ष एकजुट रहेगा, लेकिन आपसी अविश्वास और राजनीतिक अहंकार ने इस संभावना को खत्म कर दिया। नतीजा यह हुआ कि विपक्षी वोटों का विभाजन हुआ और इसका लाभ सीधे तौर पर भाजपा को मिला।

इसी तरह महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के दौरान कांग्रेस ने एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) से अलग होकर

अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। यह फैसला उस समय और भी चौंकाने वाला था, जब भाजपा के खिलाफ संयुक्त लड़ाई की बात बार-बार दोहराई जा रही थी। कांग्रेस का यह रुख उसके सहयोगियों के लिए संकेत था कि गठबंधन केवल सुविधा का मंच है, प्रतिबद्धता का नहीं।

बिहार में तस्वीर थोड़ी अलग दिखी। यहां विपक्षी महागठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन आपसी फूट, नेतृत्व की खींचतान और समन्वय की कमी ने इसे अब तक की सबसे बड़ी हार दिला दी। टिकट वितरण से लेकर प्रचार की रणनीति तक, हर स्तर पर असंतोष और अविश्वास साफ नजर आया। यह हार इसलिए भी ज्यादा चर्चा में रही क्योंकि एकजुटता के बावजूद गठबंधन जनता के बीच एक स्पष्ट, विश्वसनीय विकल्प के रूप में खुद को पेश नहीं कर सका।

2025 में इंडिया गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस लगातार गहराता गया। समय-समय पर यह मांग उठती रही कि गठबंधन का नेतृत्व केवल कांग्रेस के हाथों में न रहे। तृणमूल कांग्रेस ने इस मांग की खुलकर अगुवाई की, यह कहते हुए कि क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक ताकत और जनाधार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उधर, कांग्रेस की यह समस्या रही कि वह गठबंधन का नेतृत्व तो करना चाहती है, लेकिन उसके अनुरूप लचीलापन और सामूहिकता दिखाने में अक्सर विफल रहती है। यही कारण है कि उसके कई सहयोगी दल उसके रुख से इत्तेफाक नहीं रख पाए।

साथ ही इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेद केवल चुनावी रणनीति तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मुद्दों पर भी एकरूपता का अभाव साफ दिखा। जम्मू-कश्मीर की नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान इस संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि "एसआईआर के विरोध में कांग्रेस के उतरने का मतलब यह नहीं है कि वह हमारी भी लड़ाई हो।" यह बयान सिर्फ एक मुद्दे पर असहमति नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि गठबंधन के घटक दल अपनी-अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और राजनीतिक मजबूरियों के अनुसार फैसले ले रहे हैं। ऐसे ही विचार समय-समय पर अन्य सहयोगी दलों की ओर से भी सामने आते रहे, जिससे गठबंधन की साझा वैचारिक जमीन और भी कमजोर होती चली गई।

इसी कड़ी में यदि राहुल गांधी की भूमिका का विश्लेषण किया जाए तो 2025 उनके लिए भी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाने का वर्ष साबित हुआ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनसे यह उम्मीद की जा रही थी कि वह महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मध्यम वर्ग से जुड़े जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे, लेकिन वह अधिकतर समय चुनाव आयोग पर निशाना साधने और संवैधानिक संस्थानों को कठघरे में खड़ा करने में व्यस्त नजर आए। इससे न केवल उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हुए, बल्कि विपक्ष की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान, खासकर कर्नाटक में नेतृत्व और सत्ता संतुलन से जुड़े विवाद, का समाधान निकालने में भी वह विफल रहे। इसके अलावा पूरे वर्ष दिए गए उनके कई बयानों ने कांग्रेस ही नहीं, बल्कि उसके सहयोगी दलों की भी मुश्किलें बढ़ाईं, जिससे इंडिया गठबंधन के भीतर असहजता और अविश्वास और गहराता चला गया। देखा जाये तो साल 2025 विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता था, लेकिन यह वर्ष आपसी अविश्वास, नेतृत्व संघर्ष और रणनीतिक भ्रम की भेंट चढ़ गया।

बहरहाल, इंडिया गठबंधन अगर भविष्य में प्रासंगिक बने रहना चाहता है, तो उसे नाम से आगे बढ़कर वास्तविक राजनीतिक एकजुटता दिखानी होगी। साझा मंच, नियमित संवाद, स्पष्ट नेतृत्व संरचना और क्षेत्रीय दलों की आकांक्षाओं का सम्मान किये बिना यह गठबंधन केवल कागजी रह जाएगा। 2025 ने विपक्ष को यह सख्त संदेश दे दिया है कि बिखराव की राजनीति सत्ता का विकल्प नहीं बन सकती।

प्रेरणा

धैर्य और निरंतर प्रयास की विजय गाथा

प्राचीन काल में मगध की धरती ज्ञान, तप और अनुशासन के लिए विख्यात थी। वहीं एक शांत वन प्रांतर में स्थित था एक प्रतिष्ठित गुरुकुल, जहाँ आचार्य ज्ञानसागर जी अपने शिष्यों को केवल शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन की गूढ़ सीख भी प्रदान किया करते थे। उनका विश्वास था कि वास्तविक शिक्षा वही है जो मनुष्य के चरित्र, धैर्य और कर्मशीलता को गढ़ दे। वे कहते थे कि पुस्तकीय ज्ञान तभी सार्थक है, जब वह व्यवहार में उतर सके। इसी उद्देश्य से वे समय-समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे, ताकि उन्हें जीवन की सच्चाइयों का अनुभव कराया जा सके।

एक दिन गुरुकुल में अध्ययन का एक सत्र पूर्ण हुआ। शिष्य अपने-अपने कार्यों में लगे हुए थे। तभी आचार्य ज्ञानसागर जी ने सभी शिष्यों को अपने समीप बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, किंतु आंखों में वही करुणा और आत्मीयता झलक रही थी, जो एक सच्चे गुरु की पहचान होती है। उन्होंने शिष्यों को बांस की बनी टोकरियां वितरित कीं। शिष्य इन टोकरियों को देखकर कुछ समझ नहीं पाए। तभी आचार्य ने शांत स्वर में कहा कि गुरुकुल की सफाई के लिए नदी से जल लाना आवश्यक है और यह कार्य इन्हीं टोकरियों से करना होगा।

आचार्य की आज्ञा सुनकर शिष्य विस्मित रह गए। बांस की टोकरियां तो छिद्रों से भरी होती हैं, उनमें जल कैसे ठहर सकता है? कुछ शिष्यों ने मन ही मन इसे असंभव कार्य मान लिया। उनके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि शायद आचार्य उनकी परीक्षा ले रहे हैं, या यह कोई ऐसा आदेश है, जिसे पूरा करना संभव ही नहीं। किंतु गुरु की आज्ञा थी, इसलिए सभी शिष्य टोकरियां लेकर नदी की ओर चल पड़े।

नदी के तट पर पहुँचते ही शिष्यों ने प्रयास आरंभ किया। जैसे ही वे टोकरियों में जल भरते, पानी छिद्रों से बहकर बाहर निकल जाता। कुछ शिष्य बार-बार प्रयास करने के बाद निराश हो गए। उनके मन में यह भावना घर करने लगी कि यह कार्य व्यर्थ है। उन्होंने आपस में कहा कि यह तो असंभव है, इसमें समय और श्रम नष्ट करने का कोई लाभ नहीं। धीरे-धीरे अधिकांश शिष्य प्रयास छोड़कर गुरुकुल लौट आए, यह सोचकर कि वे आचार्य को अपनी असमर्थता बता देंगे।

किन्तु उन शिष्यों के बीच एक ऐसा भी था, जिसका मन पूरी तरह गुरु के प्रति समर्पित था। उसके हृदय में न तो संदेह था और न ही अधीरता। वह यह मानता था कि गुरु कभी भी बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं देते। उसने निश्चय किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह प्रयास करता रहेगा। उसने बार-बार नदी से जल भरकर टोकरी में डाला। हर बार पानी बह जाता, परंतु उसका धैर्य डगमगाया नहीं। उसके मन में एक ही विचार था कि निरंतर प्रयास से ही सत्य प्रकट होता है।

समय बीतता गया। सूर्य धीरे-धीरे आकाश में अपनी यात्रा करता रहा। उस शिष्य ने दिनभर वही कार्य किया। बार-बार जल भरने से बांस की टोकरियां पूरी तरह भीग गईं। बांस की सूखी तीलियां पानी सोखने लगीं, फूलने लगीं और उनके बीच के सूक्ष्म छिद्र धीरे-धीरे बंद होने लगे। शिष्य को स्वयं भी इस परिवर्तन का तुरंत आभास नहीं हुआ, किंतु उसने प्रयास नहीं छोड़ा। शाम के समय, जब उसने एक बार फिर टोकरी में जल भरा, तो आश्चर्यजनक रूप से पानी रुक गया। टोकरी अब जल को संभालने में सक्षम हो चुकी थी। उस क्षण उस शिष्य के मन में अपार आनंद और संतोष की अनुभूति हुई। वह पूरी तरह जल से भरी टोकरी लेकर गुरुकुल की ओर लौटा। उसके कदमों में थकान थी, किंतु चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। जब वह आचार्य ज्ञानसागर जी के समक्ष पहुँचा, तो आचार्य के मुख पर मंद मुस्कान फैल गई। अन्य शिष्य भी वहाँ उपस्थित थे, जो खाली हाथ लौट आए थे और अब इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे।

आचार्य ने उस शिष्य की ओर देखा और फिर अन्य शिष्यों से कहा कि उन्होंने सभी को समान कार्य सौंपा था। कार्य कठिन अवश्य था, किंतु असंभव नहीं। जो शिष्य बीच में ही हार मान गए, वे परिणाम तक नहीं पहुँच सके। जिसने धैर्य रखा, विवेक से सोचा और निरंतर प्रयास किया, वही सफल हुआ। आचार्य ने समझाया कि जीवन में अनेक बार ऐसे कार्य सामने आते हैं, जो प्रारंभ में असंभव प्रतीत होते हैं। यदि मनुष्य केवल पहली असफलता से ही हिम्मत हार जाए, तो वह कभी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं जान पाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि निरंतर सही दिशा में प्रयास करते रहना ही धैर्य है। जैसे बांस की टोकरियां बार-बार जल से भरने पर परिवर्तित हो गईं, वैसे ही मनुष्य भी सतत प्रयास से स्वयं को सक्षम बना सकता है। कठिनाइयाँ हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। गुरु की वाणी शिष्यों के हृदय में गहराई तक उतर गई।

उस दिन गुरुकुल में केवल एक कार्य की पूर्ति नहीं हुई, बल्कि सभी शिष्यों को जीवन का अमूल्य पाठ भी मिला। उन्होंने समझ लिया कि सफलता किसी जादू का परिणाम नहीं होती, बल्कि वह धैर्य, परिश्रम और अटूट विश्वास की उपज होती है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय उनसे सीखता है, वही अंततः विजयी होता है। इस प्रकार मगध के उस गुरुकुल में धैर्य और निरंतर प्रयास की यह गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई, जो यह सिखाती है कि असंभव शब्द केवल तब तक है, जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते।

सिडनी हमले से विश्व में और बढ़ेंगी मुसलमानों की मुसीबतें

मुस्लिम आतंकियों के हमलों और कट्टरपंथ सोच के कारण विश्व के कई देशों में भारी विरोध का सामना कर रहे मुस्लिमों की मुसीबतें आस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले के बाद और बढ़ेंगी। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से हनुक्का का त्यौहार मना रहे यहूदियों पर चरमपंथी आतंकवाद के नाम पर गोलियां चलाई गईं। ऐसे हमले पूर्व में युरोपीय और दूसरे देशों में हो चुके हैं। न्यू ऑरलियन्स (यूएसए) में जनवरी 1, 2025 को एक व्यक्ति ने ट्रक को पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ा दिया और फिर पुलिस से गोलीबारी की। अमरीकी संघीय जांच एजेंसी के मुताबिक यह हमला वैश्विक इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस की प्रेरणा से हुआ था।

इसी तरह फरवरी 22, 2025 को मुलहौज (फ्रांस) एक व्यक्ति ने बाजार में चाकू और पेचकस से हमला किया, जिसमें 1 व्यक्ति मारा गया और कई घायल हुए। फ्रांसीसी अधिकारियों ने इसे इस्लामिक चरमपंथ से प्रेरित बताया था। भारत के पहलगाम में हुआ हमला भी इस्लामिक चरमपंथी आतंकवाद का ही उदाहरण था। यहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने लोगों से उनके धर्म पूछ-पूछकर उन्हें गोली मारी और सीधा प्रधानमंत्री का नाम लेकर चुनौती दे रहे थे। इस समय यूरोप और पश्चिमी देशों ने निंदा तो की थी लेकिन इस्लामिक आतंकवाद का नाम नहीं लिया था। हालांकि अब यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों लोन वुल्फ हमले बढ़ रहे हैं, तो उन्हें ये दर्द समझ आ रहा है।

यूरोप में (रूस को छोड़कर), 1979 से अब तक 209 हमले हुए हैं और 802 लोगों की मौत हुई है। इसी अवधि में सबसे बुरी तरह प्रभावित यूरोपीय देश फ्रांस में 85 इस्लामी आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें 334 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस के अलावा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्निया-हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम भी प्रभावित हुए हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों में घातक हमलों की संख्या 2017 के बाद सबसे अधिक दर्ज की गई। इनमें ज्यादातर लोन वुल्फ (अकेले) हमलावर ही थे। 7 अक्टूबर, 2024 का हमला और बॉन्डी बीच का हमला विशुद्ध तौर पर यहूदियों को निशाना बनाकर किया गया। ऐसे में यूरोप को समझ में आ गया है कि ये किसी एक-दो देश की नहीं बल्कि एक विचारधारा से निपटने की लड़ाई है, जिसके लिए साथ आना ही होगा।

फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम जैसे देशों में इस्लामिक तत्व हर दूसरे दिन किसी ना किसी बात पर प्रतिकार या दंगे करने लगे हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप मोरक्को जीता तो दंगा हुआ पेरिस में, मोरक्को हारा तो पेरिस जला, जब फ्रांस फाइनल में हारा तब भी पेरिस में दंगे हुए। इंग्लैंड में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद प्रवासी भारतीयों पर स्थानीय मुस्लिमों ने हमले किये थे। जांच में यह भी सामने आया था कि अधिकाँश हमलावर और दंगाई इस्लामिक शरणार्थी थे। ऐसे में मेलबर्न से लेकर लंदन और सिडनी से लेकर पेरिस तक में प्रवासियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण वहां की सरकारों को अब इन पर एक्शन लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

एक रिपोर्ट के अनुसार इन देशों हाई माइग्रेशन रेट के कारण स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लंदन की सड़कों पर लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने एंटी-इमिग्रेशन मार्च निकाला और इस्लाम और ब्रिटेन में बढ़ती प्रवासन समस्या का मुद्दा उठाया। ब्रिटेन में पिछले साल 29 जुलाई को एक्सेल ने साउथपोर्ट में चल रही एक डांस क्लास में घुस कर कई बच्चियों को बेरहमी से चाकू मार दिया था। हमलावर ने तीन बच्चियों की हत्या कर दी थी और 10 अन्य को घायल कर दिया था। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। हमलावर मुस्लिम था। आरोपी एक्सेल के मां-बाप रवांडा से आए थे। घटना के बाद ब्रिटेन में बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

ब्रिटेन में बढ़ती मुस्लिम आबादी भी एक बड़ा मुद्दा है। अनुमान है कि साल 2035 तक ब्रिटेन की कुल आबादी में 25% मुस्लिम हो सकते हैं। ऐसे आतंकी हमलों और मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के खिलाफ प्रदर्शनकारी ब्रिटेन में अवैध अप्रवासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इनकी मांग है कि अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर किया जाए। इस साल 28 हजार से ज्यादा प्रवासी इंग्लिश चैनल के रास्ते नावों से ब्रिटेन पहुंचे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोग अवैध अप्रवासियों को शरण दिए जाने के खिलाफ हैं। हाल ही में एक इथियोपियाई अप्रवासी ने 14 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया था, जिसने लोगों के गुस्से को और बढ़ावा दिया है। सरकार और पुलिस पर आरोप कि वे अवैध आव्रजन पर नकेल कसने में असफल हैं।

मुस्लिम शरणार्थी युरोपीय देशों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। गिड़गिड़ाते हुए लाचार हालत में शरण लेने आए शरणार्थी अब इस्लाम और शरिया लागू करने के लिए धरने—प्रदर्शन कर रहे हैं। जर्मनी के हैम्बर्ग में 2000 से अधिक मुसलमानों ने रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने इस्लामवादी खिलाफत और शरिया कानून लागू करने की मांग की। रैली में शामिल भीड़ ने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। जर्मनी में बहुसंख्यक आबादी ईसाई है, जबकि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। इन मुसलमानों में सबसे ज्यादा वो थे, जो अफ्रीकी और एशियाई देशों से शरण मांगने के लिए जर्मनी पहुंचे थे। हालांकि, नागरिकता मिलते ही उनके तेवर बदल गए और अब मूल आबादी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसी इस्लामिक आतंकवाद के दंश से व्यथित हो लगभग 13 लाख लोग यूरोप में शरण लेने को विवश हुए थे, यह दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सबसे बड़ी शरणार्थी समस्या थी। शुरुआत में शरण लेने वाले अधिकाँश सीरियाई थे, लेकिन बाद में बड़ी संख्या में अफगान, नाइजीरियाई, पाकिस्तानी, इराकी और इरिट्रिया, और बाल्कन के आर्थिक प्रवासी भी इस यूरोप में शरण लेने को विवश हुए थे। यूरोप में अब तक 78,000 शरणार्थी और आप्रवासी आए हैं। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार उनमें से आधे से ज्यादा ग्रीस पहुंचे हैं।

अभियान

अहंकार से विनय तक: बाणासुर और भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीला

पुराणों में वर्णित बाणासुर और भगवान श्रीकृष्ण का युद्ध केवल अस्त्र-शस्त्रों की टकराहट नहीं है, बल्कि यह कथा मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार, भक्ति, प्रेम और धर्म के गहन संघर्ष की प्रतीक है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि जब शक्ति के साथ विवेक नहीं जुड़ता, तब वही शक्ति विनाश का कारण बनती है, और जब भक्ति में अहंकार आ जाता है, तब ईश्वर स्वयं उसे तोड़ने आते हैं। बाणासुर महाबली दैत्यराज बलि का पुत्र था। बलि जैसे महान दानी और धर्मनिष्ठ पिता का पुत्र होने के कारण उसमें अद्भुत शौर्य, अपार शक्ति और तेज था, किंतु उसके भीतर धीरे-धीरे यह भाव घर करने लगा कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाया कि स्वयं महादेव उसके नगर शोणितपुर की रक्षा करेंगे। यह वरदान उसके लिए कवच बन गया, पर उसी कवच के भीतर उसका अहंकार पलने लगा।

समय बीतने के साथ बाणासुर की शक्ति बढ़ती गई। उसकी हजार भुजाएँ उसकी सामर्थ्य का प्रतीक थीं। देवता, गंधर्व और मानव उसके नाम से भयभीत रहने लगे। परंतु बाणासुर के हृदय में शांति नहीं थी। उसे युद्ध चाहिए था, संघर्ष चाहिए था, ताकि वह अपने पराक्रम को सिद्ध कर सके। उसने एक दिन शिवजी से कहा कि उसके समान शक्तिशाली कोई योद्धा नहीं बचा, जिससे वह युद्ध कर सके। महादेव मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार का अंत निश्चित है। उन्होंने संकेत दिया कि जब समय आएगा, तब स्वयं ऐसा योद्धा सामने आएगा, जो उसके गर्व को चूर-चूर कर देगा।

इसी बीच बाणासुर की पुत्री उषा युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। वह सौंदर्य और गुणों की प्रतिमूर्ति थी। एक रात उसने स्वप्न में एक दिव्य, तेजस्वी युवक को देखा और उसके हृदय में अज्ञात प्रेम जाग उठा। वह युवक कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि द्वारकाधीश श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे। उषा की सखी चित्रलेखा, जो योग और मायाशक्ति में निपुण थी, ने उस स्वप्न का रहस्य जाना और अपनी विद्या से अनिरुद्ध को शोणितपुर ले आई। अनिरुद्ध और उषा का मिलन प्रेम की उस पवित्र धारा का प्रतीक था, जो सीमाओं, भय और नियमों से परे होती है।

कुछ समय तक यह प्रेम गुप्त रूप से फलता-फूलता रहा, परंतु सत्य अधिक दिन छिपा नहीं रहता। महल के सैनिकों ने अनिरुद्ध को देख लिया और यह समाचार बाणासुर तक पहुँच गया। क्रोध से अंधे बाणासुर ने बिना सत्य को समझे अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और नागपाश में बाँधकर कारागार में डाल दिया। यही वह क्षण था, जब उसके विनाश की घड़ी समीप आ गई। जब यह समाचार द्वारका पहुँचा, तब श्रीकृष्ण का हृदय करुणा और धर्मबोध से भर उठा। उन्होंने तुरंत सेना एकत्र की और बलराम तथा प्रद्युम्न के साथ शोणितपुर की ओर प्रस्थान किया।

युद्धभूमि में जो दृश्य उपस्थित हुआ, वह अद्भुत और भयावह दोनों था। शंखनाद, रणभेरी और अस्त्रों की गर्जना से आकाश गूंज उठा। बाणासुर अपनी विशाल सेना के साथ सामने आया, और उसकी ओर से स्वयं भगवान शिव भी उपस्थित थे, क्योंकि वे अपने भक्त को दिए वचन से बंधे थे। यह युद्ध केवल असुर और देव का नहीं था, बल्कि यह उस क्षण की परीक्षा थी, जब धर्म और भक्ति आमने-सामने खड़े होते हैं। श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से असुरों की पंक्तियाँ तोड़ दीं, बलराम ने हल से पर्वतों जैसे योद्धाओं को धराशायी कर दिया। पृथ्वी कांपने लगी, आकाश में बिजली कौंधने लगी, और देवता भी इस युद्ध को विस्मय से देखने लगे।

जब बाणासुर की सेना पराजय के कगार पर पहुँची, तब स्वयं भगवान शिव रणभूमि में उतरे। यह दृश्य अत्यंत दिव्य था, क्योंकि एक ओर नारायण थे और दूसरी ओर महादेव। दोनों के बीच कोई वैर नहीं था, केवल लीला थी, धर्म की मर्यादा थी। शिवजी के अस्त्रों का उत्तर श्रीकृष्ण ने शांति और संयम से दिया। अंततः श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की हजारों भुजाएँ काट दीं, केवल चार हाथ शेष छोड़े, ताकि उसका जीवन बना रहे। तब शिवजी ने हस्तक्षेप कर अपने भक्त के लिए करुणा की याचना की। श्रीकृष्ण ने स्वीकार किया, क्योंकि धर्म का अर्थ केवल दंड नहीं, बल्कि सुधार भी है।

पराजित बाणासुर का अहंकार चूर हो चुका था। उसने शिव और कृष्ण दोनों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि शक्ति बिना विवेक के अंधकार बन जाती है। इसके बाद अनिरुद्ध और उषा का विवाह विधिपूर्वक सम्पन्न हुआ और शोणितपुर में आनंद और शांति का वातावरण लौट आया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची विजय वही है, जिसमें अहंकार हारता है और विनय जीतता है। धर्म, प्रेम और भक्ति जब एक साथ चलते हैं, तब जीवन में संतुलन और शांति स्थापित होती है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

गुजरात में प्रशासनिक लापरवाही ने ली एक जवान की जान मैनहोल में गिरने से रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे की मौत

(जीएनएस)। वडोदरा। गुजरात के वडोदरा शहर में एक भयानक हादसा उस समय सामने आया, जब एक युवा विवाहित युवक मैनहोल में गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। शुक्रवार की शाम करीब साढ़े सात बजे यह दुर्घटना हुई, और घटना ने पूरे शहर में प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मृतक विपुल सिंह झाला, जो एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे थे, अपने साले के साथ चाइनीज खाने के लिए मांजलपुर पानी की टंकी के पास गए थे। इसी दौरान मंजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास खुले ड्रेनेज मैनहोल में गिरने से विपुल की जान चली गई।

जानकारी के अनुसार, विपुल का मोबाइल भी उनके साथ नीचे गिर गया था, जिससे उन्हें मैनहोल से बाहर निकालने में काफी समय लग गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मैनहोल से विपुल को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वह मृत हो चुके थे। यह दुखद घटना वडोदरा नगर निगम (वीएमसी) के वार्ड नंबर 17 में हुई, जो गुजरात में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल का क्षेत्र है। स्थानीय लोगों में वीएमसी और विधायक के खिलाफ भारी आक्रोश है, और उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

यह हादसा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के वडोदरा दौरे के कुछ घंटे बाद हुआ, जब उन्होंने शहर में 957 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री के दौरे के तुरंत बाद हुई इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है

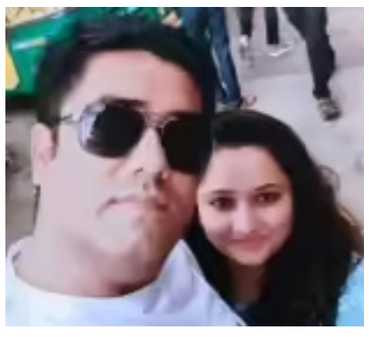

कि खुले मैनहोल की वजह से एक पूरे परिवार की खुशियां छिन गईं।

पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी के अनुसार, विपुल सिंह झाला के पिता का निधन कोरोना काल में हुआ था। अब विपुल की मौत से परिवार को बड़ा नुकसान सहना पड़ा, क्योंकि छोटे बेटे सिर से पिता का साया भी छिन गया। परिवार का आरोप है कि ड्रेन का ढक्कन खुला कैसे रह सकता है और यह किस तरह से वीएमसी की लापरवाही का परिणाम है।

स्थानीय लोगों और समाजिक कार्यकर्ताओं ने इस हादसे की निंदा करते हुए कहा कि शहर में खुले मैनहोल और खराब रखरखाव वाली ड्रेनेज प्रणाली लगातार लोगों के जीवन के लिए खतरा बनी हुई है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई करने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

इस घटना ने नगर निगम और स्थानीय प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी विकास और सुरक्षा मानकों की उपेक्षा कई बार मानव जीवन को सीधे खतरे में डाल देती है। खुला छोड़ा गया मैनहोल न केवल हादसों का कारण बनता है, बल्कि यह शहर की सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

वडोदरा में यह घटना शहरवासियों के लिए चेतावनी है कि नगर निगम और संबंधित प्रशासनिक विभागों को अपने जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहना चाहिए। खुले मैनहोल, टूटी सड़कों और खराब रखरखाव के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन इस बार यह एक जवान के जीवन को निगल गया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया कि प्रशासनिक लापरवाही न केवल एक परिवार को प्रभावित करती है, बल्कि समाज में असंतोष और भय का माहौल भी पैदा करती है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कानूनी दायरे में लाया जाए। विपुल सिंह झाला की मौत ने वडोदरा में शहरी सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और प्रशासन के लिए यह चेतावनी है कि ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।

सूरत टेक्सटाइल मार्केट में अनोखे 'प्याऊ' का उद्घाटन, राहगीरों और व्यापारियों को मिलेगा निःशुल्क शीतल जल

(जीएनएस)। सूरत। शहर में जनहित और सामाजिक सेवा की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए सूरत टेक्सटाइल मार्केट गेट पर अनोखे "प्याऊ" का उद्घाटन किया गया। इस प्याऊ की स्थापना साकेत ग्रुप और चाय पे चर्चा चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त प्रयास से की गई है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों, व्यापारियों, मजदूरों और राहगीरों को गर्मी में ताजगी देने वाला निःशुल्क शीतल पेयजल उपलब्ध कराना है।

शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजे विधायक संगीता पाटिल ने इस प्याऊ का शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) के अध्यक्ष कैलास हाकिम, समाजसेवी एवं कपड़ा व्यापारी नरेन्द्र साबू, स्थानीय पुलिस अधिकारी, कपड़ा व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह में उपस्थित लोगों ने इस पहल की सराहना की और इसे जनकल्याण की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया।

इस अवसर पर स्टीम हाउस के संस्थापक और समाजसेवी सांवर प्रसाद बुधिया ने कहा कि "शीतल जल सबके लिए" के संदेश के साथ शुरू की गई यह पहल खासतौर पर गर्मी के मौसम में लोगों के लिए राहत का काम करेगी। उन्होंने बताया कि टेक्सटाइल मार्केट जैसे व्यस्त इलाके में इस प्याऊ से रोजाना हजारों लोग लाभान्वित होंगे।

साकेत ग्रुप की ओर से सांवर प्रसाद बुधिया और चाय पे चर्चा चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुभाष डावर ने इस सेवा प्रकल्प को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि यह प्याऊ केवल पानी उपलब्ध कराने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज में सहयोग, मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को भी दर्शाता है।

स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने इस पहल की बहुत प्रशंसा की। मार्केट के कई व्यापारी और कर्मचारी इस प्याऊ का उपयोग पहले ही करने लगे हैं और इसे गर्मी और धूल-धक्के से राहत देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसके अलावा, राहगीरों और गरीबों के लिए यह पानी का निःशुल्क स्रोत उपलब्ध कराता है, जिससे शहर में सामाजिक सहयोग और मानवता की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा।

विधायक संगीता पाटिल ने कहा कि ऐसे सामाजिक पहल से शहरवासियों में सहयोग और जागरूकता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहलों से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं और यह नागरिकों के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाती हैं।

साकेत ग्रुप और चैरिटेबल ट्रस्ट का मानना है कि आने वाले समय में इस तरह के और प्याऊ स्थापित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को गर्मी में ताजगी और शीतल जल मिल सके। उन्होंने उपस्थित लोगों से इस प्याऊ का ध्यान रखने और इसे सही तरीके से उपयोग करने का अनुरोध भी किया।

यह पहल न केवल सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह शहर के व्यस्त व्यापारिक क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों और काम करने वाले मजदूरों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आई है। स्थानीय लोग और व्यापारी इसे शहर में सामुदायिक सहयोग की दिशा में एक सराहनीय कदम मान रहे हैं।

सूरत टेक्सटाइल मार्केट में स्थापित यह प्याऊ इस बात का उदाहरण है कि कैसे निजी संगठन और समाजसेवी संस्था मिलकर समाज के लिए ठोस और उपयोगी कदम उठा सकते हैं। यह प्रकल्प भविष्य में अन्य शहरों और व्यस्त बाजार क्षेत्रों में भी लागू किए जाने की संभावना रखता है।

सूरत में भदोई सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद ने लक्ष्मीपति प्रोसेस हाउस का दौरा कर साड़ी उद्योग की कार्यप्रणाली का लिया जायजा

सूरत। उत्तर प्रदेश के भदोई से लोकसभा सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद ने शनिवार को सूरत के पांडेसरा क्षेत्र में स्थित लक्ष्मीपति प्रोसेस हाउस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने साड़ी निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं और उद्योग की कार्यप्रणाली का नजदीकी अवलोकन किया।

सांसद डॉ. बिंद का स्वागत लक्ष्मीपति ग्रुप के चेयरमैन संजय सरावगी और उद्योग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। दौरे के दौरान सांसद ने मिल परिसर का निरीक्षण किया और कच्चे माल से लेकर तैयार साड़ी तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने यह भी देखा कि किस प्रकार विभिन्न मशीनों और शिल्पियों के सामंजस्य से उच्च गुणवत्ता वाली साड़ियाँ तैयार की जाती हैं।

डॉ. बिंद ने इस अवसर पर कहा कि सूरत का वस्त्र उद्योग न केवल स्थानीय रोजगार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम योगदान देता है। उन्होंने लक्ष्मीपति ग्रुप की उत्पादन तकनीक और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली की सराहना की और कहा कि इस उद्योग की कार्यकुशलता देश के अन्य क्षेत्रों के लिए प्रेरणास्त्रोत है। सांसद ने यह भी जोर देकर कहा कि ऐसे दौरे न केवल उद्योग की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करते हैं, बल्कि इससे नीति निर्माण और विकास योजनाओं के लिए जरूरी जानकारी भी जुटती है। उन्होंने उद्योग से जुड़े कर्मचारियों और तकनीशियनों से भी बातचीत की और उनके सुझावों को सुना।

लक्ष्मीपति ग्रुप की ओर से सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद को सम्मानित किया गया और उन्हें उद्योग की उपलब्धियों और उत्पादन क्षमता पर संक्षिप्त जानकारी दी गई। ग्रुप के अधिकारियों ने बताया कि साड़ी निर्माण में न केवल पारंपरिक शिल्प कौशल का उपयोग किया जाता है, बल्कि आधुनिक तकनीकी मशीनों और डिजाइन सॉफ्टवेयर की मदद से उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाया गया है।

इस अवसर पर सांसद ने कहा कि सूरत का वस्त्र उद्योग देशभर में अपनी विशिष्टता और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस उद्योग की निरंतर प्रगति से न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि देश का वस्त्र निर्यात भी बढ़ेगा। सांसद डॉ. बिंद का यह दौरा इस बात का उदाहरण है कि कैसे नीतिनिर्माता और उद्योगपति मिलकर देश के प्रमुख उद्योगों की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं और उनके विकास में सहयोग कर सकते हैं। इस दौरान सांसद ने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार उद्योगों के विकास और तकनीकी उन्नयन के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। सूरत के साड़ी उद्योग के अधिकारी और कर्मचारी सांसद के दौरे से उत्साहित दिखाई दिए और उन्होंने इस अवसर को अपने उद्योग की उपलब्धियों को उजागर करने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। इस दौरे से उद्योग और सरकार के बीच बेहतर संवाद और सहयोग की संभावनाएं भी उजागर हुईं।

अहमदाबाद में व्यापारियों को करोड़ों की चपत, कपड़ा और लोहे के कारोबारी ठगे गए – तीन मामले दर्ज

(जीएनएस)। अहमदाबाद। शहर के कपड़ा और लोहे के पाइप-पतरे का व्यापार करने वाले स्थानीय व्यापारियों को करोड़ों रुपए की चपत लगने की घटना सामने आई है। इस सिलसिले में पुलिस ने क्राइम ब्रांच थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं और मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा की न्यू क्लॉथ मार्केट इकाई को सौंपी गई है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली निवासी व्यापारी दंपती संजय पांडे और निरुपमा पांडे ने तीन अन्य व्यापारियों – महेश जवर, मयंक खन्ना और पुरुषोत्तम शर्मा के साथ मिलकर अहमदाबाद के कपड़ा (डेनिम फेब्रिक) व्यापारी नीरव कनोडिया और दो अन्य व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया। नीरव कनोडिया ने 26 दिसंबर को क्राइम ब्रांच में पांचों के खिलाफ विश्वासघात और ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। नीरव के बयान के अनुसार, अप्रैल 2019 में संजय और निरुपमा पांडे अहमदाबाद आए और खुद को बड़े व्यापारियों के रूप में पेश किया। उन्होंने 90 दिन में बिल का भुगतान करने का वादा किया और स्थानीय व्यापारियों का विश्वास जीत लिया। इसके बाद 27 अप्रैल 2019 से 6 जून 2022 के बीच उन्होंने कुल 8.34 करोड़ रुपए का माल ऑर्डर देकर खरीदा। हालांकि, 90 दिन की समयसीमा के बजाय उन्होंने 6.76 करोड़ रुपए ही समय पर चुकाए और बाकी 1.58 करोड़ रुपए बार-बार मांगने पर भी भुगतान नहीं किया।

नीरव ने बताया कि वर्ष 2024 में जब

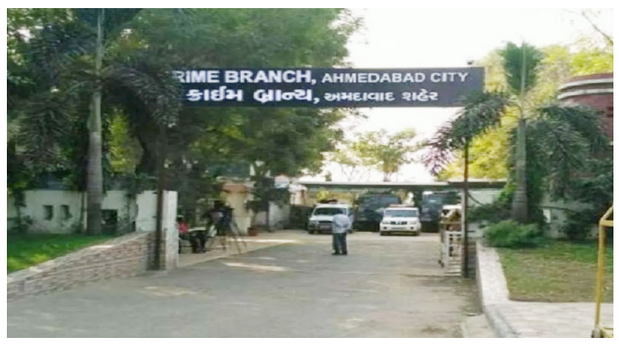

उन्होंने दिल्ली में पते के अनुसार दंपती का पता लगाने का प्रयास किया, तो पता चला कि उनकी दुकान बंद कर दी गई थी और वे कहीं और चले गए। जांच में यह भी सामने आया कि संजय और निरुपमा ने नारोल में व्यापार करने वाले अन्य व्यापारियों को भी धोखा दिया। आदित्य अग्रवाल से 64.98 लाख रुपए का माल बिना भुगतान लिए खरीदा गया, मयंक खन्ना और पुरुषोत्तम शर्मा के माध्यम से 9.17 लाख रुपए का माल बिना भुगतान के लिया गया, जबकि रमेश तायल से 31.85 लाख रुपए का माल लेने के बाद भुगतान नहीं किया गया। इस मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ ठगी, विश्वासघात और आर्थिक अपराध की धाराओं के तहत तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला पहले से संगठित और सुनियोजित ठगी का प्रतीक है, जिसमें दिल्ली और अहमदाबाद के बीच व्यापारिक नेटवर्क का दुरुपयोग किया गया।

नीरव कनोडिया ने स्थानीय व्यापारियों को चेतावनी दी है कि ऐसे धोखाधड़ी के मामलों में सतर्क रहें और बड़े लेनदेन के समय लिखित अनुबंध और सुरक्षित भुगतान के तरीके अपनाएं। क्राइम ब्रांच की टीम आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा के सहयोग से आरोपियों की सम्पत्तियों और लेनदेन का विस्तृत विवरण जुटा रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े पैमाने पर व्यापारिक ठगी का यह मामला व्यापारियों के लिए गंभीर चेतावनी है। केवल विश्वास और वादों पर भरोसा करना अब सुरक्षित नहीं रहा है, और कानूनी और वित्तीय सावधानियों के बिना कोई भी व्यापारी करोड़ों का नुकसान उठा सकता है। इस घटना ने अहमदाबाद के व्यापारिक समुदाय में चिंता की लहर दौड़ा दी है और प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग उठी है। मामले की जांच पूरी होने के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की संभावना है, ताकि अन्य व्यापारियों के लिए एक मिसाल कायम हो और आर्थिक अपराधों को रोकने में मदद मिले।

अहमदाबाद क्षेत्र से 150 से अधिक ट्रेनों का संचालन होगा संभव,अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेनों का लोड कम होगा, संचालन होगा और भी सुगम

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के वटवा में लगभग 3 किमी का एक मेगा कोचिंग टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा, जिसके माध्यम से अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेनों का अत्यधिक लोड काफी हद तक कम होगा और पूरे क्षेत्र में ट्रेन संचालन क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी। यह परियोजना मंडल की 2.5 गुना ट्रेन हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।

वटवा टर्मिनल की मुख्य संरचना और आधुनिक सुविधाएँ

▸▸ वटवा का यह मेगा टर्मिनल लगभग 3 किमी लंबा होगा, जिसकी चौड़ाई LC-305 पर 76 मीटर, ROB-713 (SP रिंग रोड) पर 300 मीटर तथा खारी ब्रिज नं. 711 पर 118 मीटर रहेगी।

▸▸ टर्मिनल में कुल 12 पिट लाइनें बनाई जा रही हैं, जिनसे ट्रेनों का गहन व नियमित मेंटेनेंस आसानी से संभव होगा।

▸▸ 29 स्टेबलिंग लाइनें उपलब्ध कराई जाएँगी, जिनमें खाली रेक सुरक्षित खड़े किए जा सकेंगे।

▸▸ 2 वॉशिंग लाइनें बनाई जाएँगी, जिनसे रेक की तेज़ और निरंतर सफाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

▸▸ 2 सिक लाइनें (600 मीटर) बनाई जा रही हैं, जहाँ खराब कोचों की मरम्मत और तकनीकी सुधार किए जा सकेंगे।

▸▸ 6 नए अतिरिक्त प्लेटफॉर्म बनाए जाएँगे, जिससे प्लेटफॉर्मों की कुल संख्या 9 हो जाएगी और ट्रेनों का आरंभ व समाप्ति अधिक सुव्यवस्थित होगी।

▸▸ वटवा टर्मिनल के पूर्ण संचालन के बाद प्रतिदिन 36 जोड़ी ट्रेनों का प्राइमरी मेंटेनेंस, 15 ट्रेनों की प्लेटफॉर्म रिटर्न सुविधा और कुल 51 ट्रेनों का संचालन संभव होगा।

▸▸ अकेले वटवा टर्मिनल ही मंडल की कुल क्षमता वृद्धि में लगभग 85% योगदान देगा।

अहमदाबाद मंडल में व्यापक क्षमता वृद्धि–सभी स्टेशनों पर तेजी से चल रहा विकास

▸▸ वटवा के साथ-साथ अहमदाबाद, साबरमती, असारवा और गांधी नगर कैपिटल स्टेशनों पर भी बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन कार्य जारी हैं, जो पूरे नेटवर्क को मजबूत बनाएँगे।

▸▸ सभी कार्य पूर्ण होने पर मंडल की ट्रेन ओरिजिनेशन क्षमता औसत 58 से बढ़कर 150 प्रतिदिन हो जाएगी, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि होगी।

▸▸ अहमदाबाद स्टेशन पर ट्रेन संचालन क्षमता 38 ट्रेनों से बढ़कर 45–50 ट्रेनों प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी।

▸▸ साबरमती स्टेशन पर यह क्षमता 20 से बढ़कर 27–28 ट्रेन प्रतिदिन होगी।

▸▸ असारवा स्टेशन पर क्षमता 6 से बढ़कर 11–12 ट्रेन प्रतिदिन तक बढ़ेगी।

▸▸ गांधीनगर कैपिटल स्टेशन की क्षमता 6 से बढ़कर 8–10 ट्रेन प्रतिदिन तक पहुँच जाएगी।

▸▸ वटवा स्टेशन की संचालन क्षमता सबसे अधिक वृद्धि के साथ 6 से बढ़कर 56–57 ट्रेन प्रतिदिन तक पहुँचेगी।

यात्रियों को बड़े लाभ और रणनीतिक नेटवर्क सुधार

▸▸ क्षमता वृद्धि से यात्रियों को प्रतिदिन की यात्री वहन क्षमता 1,02,000 से बढ़कर 2,62,000 प्रतिदिन (लगभग 2.5 गुना) तक का लाभ मिलेगा।

▸▸ अधिक संख्या में एक्सप्रेस, MEMU, फेस्टिवल स्पेशल और लंबी दूरी की ट्रेन सेवाओं की शुरुआत संभव होगी।

▸▸ पिट लाइन बनने से 23-कोच LHB रेक, वंदेभारत एवं अमृत भारत जैसी ट्रेनों का मेंटेनेंस संभव होगा जिससे ट्रेनों की उपलब्धता बढ़ेगी।

▸▸ अहमदाबाद और साबरमती यार्ड में भीड़ कम होने से ट्रेनों की समयपालनता में वृद्धि होगी।

▸▸ अहमदाबाद यार्ड रीमॉडलिंग, साबरमती में नई पिट लाइन व प्लेटफॉर्म निर्माण, असारवा–साबरमती Y-कनेक्शन तथा गांधीग्राम–साबरमती–खोड़ियारY-कनेक्शन जैसे प्रमुख नेटवर्क सुधार कार्य ट्रेन मूवमेंट को तेज़, सुरक्षित और निर्बाध बनाएँगे।

इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने पर अहमदाबाद मंडल पश्चिम रेलवे का सबसे सक्षम, आधुनिक और भविष्य-उन्मुख टर्मिनल क्लस्टर बनकर उभरेगा, जो प्रतिदिन 150 ट्रेनों का संचालन दक्षता से कर सकेगा। यह यात्रियों की सुविधा और सेवा गुणवत्ता में ऐतिहासिक सुधार लाएगा। साथ ही अहमदाबाद मण्डल पर कई स्टेशनों पुनर्विकास का कार्य चल रहा है जिससे स्टेशनों की संचालन क्षमता बढ़ेगी।

▸▸ अहमदाबाद स्टेशन का पुनर्विकास तीव्र गति से चल रहा है। स्टेशन बिल्डिंग की साउथ विंग का कार्य जून-जुलाई 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।

▸▸ साबरमती स्टेशन का पुनर्विकास भी तेजी से चल रहा है। इसका कार्य भी नववर्ष 2026 में पूर्ण हो जाएगा।

▸▸ न्यू भुज रेलवे स्टेशन का उन्नयन कार्य तेज़ी से प्रगति पर है। इस परियोजना की स्वीकृत लागत लगभग 200 करोड़ है, इसका 75% से अधिक कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है। अप्रैल 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।

▸▸ अहमदाबाद मण्डल पर अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आसारवा, मणिनगर, चांदलोडिया, वटवा, कलोल, सामाख्याली, धांगध्रा, भचाऊ, गांधीधाम, सिद्धपुर, उंझा, महेसाणा, पालनपुर, पाटन, हिम्मतनगर और भीलड़ी स्टेशनों का पुनर्विकास का कार्य तेजी से चल रहा है।

भावनगर मंडल से होकर चलने वाली 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु भावनगर मंडल से होकर चलने वाली 4 जोड़ी "स्पेशल ट्रेनों" के फेरे विस्तारित किए गए हैं। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. ट्रेन संख्या 09208/09207 भावनगर-बान्द्रा-भावनगर साप्ताहिक स्पेशल

ट्रेन संख्या 09207 बांद्रा टर्मिनस-भावनगर स्पेशल, जिसे पहले 26 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 27 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09208 भावनगर-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल, जिसे पहले 25 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 27 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

2. ट्रेन संख्या 09212/09211 बोटाद-गांधीग्राम-बोटाद दैनिक स्पेशल (अनारक्षित)

ट्रेन संख्या 09211 गांधीग्राम-बोटाद स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09212 बोटाद-गांधीग्राम स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

3. ट्रेन संख्या 09215/09216 गांधीग्राम-भावनगर-गांधीग्राम दैनिक स्पेशल (अनारक्षित)

ट्रेन संख्या 09216 भावनगर-गांधीग्राम स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09215 गांधीग्राम-भावनगर स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

4.ट्रेन संख्या 09529/09530 धोला-भावनगर-धोला दैनिक स्पेशल (अनारक्षित)

ट्रेन संख्या 09529 धोला-भावनगर स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09530 भावनगर-धोला स्पेशल जिसे पहले 31 दिसंबर, 2025 तक अधिसूचित किया गया था, अब उसे 28 फरवरी, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

गौरतलब है कि धोला-भावनगर-धोला दैनिक स्पेशल ट्रेन भावनगर टर्मिनस स्टेशन पर पीट लाइन की मरम्मत हेतु चल रहे कार्य की वजह से 25 जनवरी, 2026 तक के लिए निरस्त की गई है, इस कारण से यह ट्रेन कार्य पूर्ण होने के पश्चात 26 जनवरी से 28 फरवरी, 2026 तक के लिए विस्तारित की गई है।

नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

- टूरिज्म, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाइड्रो एनर्जी एवं मैन्युफैक्चरिंग तथा एजुकेशन सेक्टर में सहभागिता पर परामर्श
- प्रधानमंत्री के दिशादर्शन में गुजरात द्वारा बहुविध क्षेत्रों में किए गए विकास से प्रभावित हुए नेपाल के राजदूत

(जीएनएस)। गांधीनगर : भारत में नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा ने शनिवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की।

डॉ. शर्मा नेपाल के टूरिज्म प्रवोशन के लिए गुजरात की यात्रा पर आए हैं। aइस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री से यह शिष्टाचार भेंट-बैठक आयोजित की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशादर्शन में गुजरात द्वारा टूरिज्म सेक्टर में जो विश्व आकर्षण स्थापित किए हैं, उसकी डॉ. शर्मा ने प्रशंसा की। उन्होंने विशेष रूप से टूरिज्म, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाइड्रो एनर्जी एवं मैन्युफैक्चरिंग तथा एजुकेशन सेक्टर में सहभागिता पर मुख्यमंत्री के साथ परामर्श किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग हब बने होने तथा सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स

में भी अग्रणी बनने को सज्ज हुए होने का विवरण दिया।

इसके अलावा; मुख्यमंत्री ने नेपाल के राजदूत के समक्ष भूमिका दी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिट, सफेद रण जैसे पर्यटन स्थलों और सोमनाथ, द्वारका तथा अंबाजी जैसे आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों के साथ गुजरात विश्वभर के पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बना है।

नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर प्रसाद शर्मा तथा मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के बीच इस शिष्टाचार भेंट-बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, उद्योग विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती ममता वर्मा, उद्योग आयुक्त श्री पी. स्वरूप तथा नेपाली प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी सहभागी हुए।

भारतीय रेलवे की अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों में रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता दोगुनी करने की योजना

प्रमुख शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने, भीड़भाड़ कम करने और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार लाने के लिए किया जाएगा: रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव

(जीएनएस)। यात्रा की मांग में लगातार हो रही तीव्र वृद्धि को देखते हुए, अगले 5 वर्षों में प्रमुख शहरों की नई रेल गाड़ियों के संचालन की क्षमता को वर्तमान स्तर से दोगुना करना आवश्यक है। आगामी वर्षों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। वर्ष 2030 तक संचालन क्षमता को दोगुना करने के लिए निम्नलिखित कार्य शामिल होंगेः

i. मौजूदा टर्मिनलों को अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइन, पिट लाइन और पर्याप्त शंटिंग सुविधाओं से सुसज्जित करना।

ii. शहरी क्षेत्र में और उसके आसपास नए टर्मिनलों की पहचान और निर्माण करना।

iii. मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित रखरखाव सुविधाएं।

iv. विभिन्न स्थानों पर रेल गाड़ियों की

बढ़ती संख्या की व्यवस्था करने के लिए यातायात सुविधा कार्यों, सिग्नलिंग उन्नयन और मल्टीट्रैकिंग के माध्यम से अनुभागीय क्षमता में वृद्धि करना।

देश के 48 प्रमुख शहरों की एक व्यापक योजना विचाराधीन है। इस योजना में निर्धारित समय सीमा के भीतर रेल गाड़ियों की संचालन क्षमता को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियोजित, प्रस्तावित या पहले से स्वीकृत कार्यों को शामिल किया जाएगा।

क्षमता को वर्ष 2030 तक दोगुना करने की योजना है, लेकिन यह आशा है कि अगले 5 वर्षों में क्षमता में क्रमिक वृद्धि की जाएगी ताकि क्षमता वृद्धि के लाभ तुरंत प्राप्त किए जा सकें। इससे आने वाले वर्षों में यातायात की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने में सहायता मिलेगी। योजना में कार्यों को तीन श्रेणियों, अर्थात् तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक में वर्गीकृत किया जाएगा।

केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "हम यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए विभिन्न शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का विस्तार कर रहे हैं और अनुभागीय एवं परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इस कदम से हमारे रेलवे नेटवर्क का उन्नयन होगा और राष्ट्रव्यापी संपर्क सुविधा में सुधार होगा।"

सूरत में भारत विकास परिषद, पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय अधिवेशन 3–4 जनवरी को आयोजित, सेवा और संस्कार के माध्यम से समाज निर्माण की दिशा में जोर

(जीएनएस)। सूरत। सेवा और संस्कार के माध्यम से स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से भारत विकास परिषद, पश्चिम क्षेत्र का क्षेत्रीय अधिवेशन आगामी 3 एवं 4 जनवरी 2026 को सूरत स्थित वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया जाएगा। यह अधिवेशन परिषद के पश्चिम क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं, विद्यार्थियों और समाजसेवियों को एक मंच पर जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर होगा।

अधिवेशन की जानकारी देते हुए भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री दुर्गा दत्त शर्मा ने बताया कि परिषद देशभर में 1800 से अधिक शाखाओं और दो लाख से अधिक सदस्यों के माध्यम से सुसंस्कृत समाज निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है। परिषद अपने संस्कार प्रकल्पों के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का सिंचन करती है। इसके साथ ही विकलांगों के लिए सहायता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भी परिषद सक्रिय है। उन्होंने बताया कि महिला कार्यों के अंतर्गत परिषद आत्मनिर्भर भारत, कौशल वर्धन, संस्कार एवं धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ एनीमिया मुक्त भारत अभियान भी संचालित कर रही है।

राष्ट्रीय महामंत्री ने यह भी बताया कि परिषद पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में पौधारोपण, जल संचय, वायु प्रदूषण नियंत्रण और वेस्ट मैनेजमेंट जैसी गतिविधियों के जरिए जागरूकता फैलाती है। इसके अलावा परिषद पारिवारिक मिलन और राष्ट्रीय पर्वों के आयोजन में भी सक्रिय है, जिससे समाज में आपसी सहयोग और एकजुटता को बल मिलता है।

भारत विकास परिषद अपने संगठनात्मक ढांचे के अंतर्गत देशभर में 10 क्षेत्रों एवं 79 प्रांतों के माध्यम से चार स्तरीय कार्यपद्धति पर कार्य कर रहा है। पश्चिम क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा शामिल हैं, जहां परिषद की कुल 10 प्रांत और 154 शाखाएं सक्रिय हैं। क्षेत्रीय अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के बीच सेतु का निर्माण करना, नए कार्यक्रमों की योजना बनाना, प्रांतीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं में से क्षेत्रीय विजेताओं का चयन करना और कार्यकर्ता निर्माण हेतु अभ्यास वर्ग आयोजित करना है।

पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष एल. आर. जाजू ने बताया कि परिषद बच्चों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए 'भारत को जानो' प्रतियोगिता का आयोजन करती है। इस क्षेत्रीय अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल, गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुरेश जैन सहित अनेक राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी शामिल होंगे। अधिवेशन में पश्चिम क्षेत्र से लगभग 800 से अधिक सदस्यों की सहभागिता होने की संभावना है। दक्षिण गुजरात प्रांत के अध्यक्ष धर्मेश शाह, सचिव पुष्पक काका, वित्त सचिव प्रधुमन जरीवाला, कौस्तुभ परिख, हितेश अग्रवाल, विपुल जरीवाला, भावेश ओझा सहित अनेक पदाधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री दुर्गा दत्त शर्मा ने कहा कि परिषद के ये अधिवेशन कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों को मार्गदर्शन देने के साथ-साथ नए प्रकल्पों और कार्यक्रमों के लिए रणनीति तैयार करने का मंच हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिण गुजरात प्रांत के अंतर्गत गुजरात के 9 जिलों में 11 शाखाएं सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से 15,000 से अधिक विद्यार्थी संस्कार प्रकल्पों से जुड़े हुए हैं। सेवा कार्यों में जनजातीय क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया जा रहा है, और पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए उदाहरणीय कार्यों के चलते परिषद शासकीय और अशासकीय संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर सक्रिय भूमिका निभा रही है। संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान परिषद का लक्ष्य प्रत्येक जिले को 'कार्ययुक्त जिला' बनाना है, जिससे प्रत्येक जिले में सेवा, संस्कार और समाज निर्माण की गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित हो सकें।

इस क्षेत्रीय अधिवेशन को परिषद की सेवा, संस्कार और समाज निर्माण के मूल उद्देश्य को मजबूती देने वाला कार्यक्रम माना जा रहा है। इसके माध्यम से न केवल पश्चिम क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को एक मंच मिलेगा, बल्कि युवा पीढ़ी में नैतिक मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और अभ्यास वर्गों के माध्यम से परिषद भविष्य के समाजसेवियों और कार्यकर्ताओं को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएगी।

इस प्रकार, 3 और 4 जनवरी को आयोजित होने वाला भारत विकास परिषद, पश्चिम क्षेत्र का यह क्षेत्रीय अधिवेशन समाज सेवा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक प्रेरक और ऐतिहासिक आयोजन साबित होने जा रहा है।

सूरत में पारीक संवाद सेतु द्वारा बीकानेर छ न्याती ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों का भव्य स्वागत और समाजिक सहयोग की दिशा में चर्चा

(जीएनएस)। सूरत। पारीक संवाद सेतु, सूरत की ओर से सूरत प्रवास पर आए बीकानेर छ न्याती ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों का पारंपरिक रूप से दुपट्टा ओढ़ाकर भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में समाज के विकास, संगठन को सशक्त बनाने और प्रगतिशील दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। बीकानेर पारीक समाज के अग्रणी समाजसेवी संपत पारीक ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े पारीक बंधुओं के लिए शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के क्षेत्र में अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि समाज के प्रत्येक सदस्य को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर बीकानेर छ न्याती ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पराशर शर्मा ने बीकानेर में निर्माणाधीन ब्राह्मण समाज भवन के लिए सूरत विप्र समाज से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि समाज के सदस्य जब एकजुट होकर प्रयास करेंगे तो न केवल भवन निर्माण में सफलता मिलेगी, बल्कि समाज के सामूहिक विकास की दिशा में भी स्थायी कदम उठाए जा सकेंगे।

कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रमुख समाजसेवियों में हनुमान साकी, जय दयाल शर्मा, रमेश पारीक, सूरत पारीक विकास ट्रस्ट के महामंत्री प्रदीप पारीक, बनवारी पारीक, सारस्वत समाज के अग्रणी श्याम तावणिया सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल थे। उन्होंने अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा करते हुए समाज के सामूहिक विकास और भाईचारे को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया।

सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से यह कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। इसमें न केवल अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया, बल्कि समाज के हित में आने वाले समय में किए जाने वाले प्रकल्पों और सहयोग की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। सभी उपस्थित सदस्यों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक उत्थान जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।

कार्यक्रम के अंत में रामावतार पारीक ने पारीक संवाद सेतु परिवार की ओर से सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सूरत पारीक समाज द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी दी और समाज हित में सदैव सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि समाजिक सेवा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक परंपरा है, जिसे नई पीढ़ी तक पहुँचाना और इसे निरंतर बनाए रखना सभी सदस्यों का दायित्व है।

इस अवसर ने यह संदेश भी दिया कि पारीक समाज केवल अपने सदस्यों तक सीमित नहीं रहकर समाज के व्यापक हित में कार्य कर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में उठाए गए कदम अन्य समुदायों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। समाज के वरिष्ठ सदस्य और युवा कार्यकर्ता एक साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि समाज के हर सदस्य को विकास और अवसरों तक समान पहुंच मिले।

सामाजिक सहभागिता, संगठनात्मक मजबूती और पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण के दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। पारीक संवाद सेतु के नेतृत्व और समाज के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी ने इसे न केवल स्वागत और सम्मान का अवसर बनाया, बल्कि समाजिक एकजुटता और भविष्य की योजनाओं के लिए मार्गदर्शन का मंच भी प्रस्तुत किया। इस प्रकार सूरत में आयोजित यह आयोजन समाज के विकास, सेवा और एकजुटता की दिशा में एक प्रेरक कदम साबित हुआ।

असम में विधानसभा चुनाव से पहले 10.56 लाख वोटरों के नाम कटने से बढ़ी राजनीतिक हलचल

(जीएनएस)। गुवाहाटी। असम में विधानसभा चुनाव से लगभग छह महीने पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण (स्पेशल रिवीजन) पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया में कुल 10,56,291 लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल और चर्चा तेज हो गई है। स्पेशल रिवीजन के तहत वोटर लिस्ट की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर व्यापक सत्यापन किया गया, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को जारी ड्राफ्ट वोटर रोल के अनुसार, असम में कुल 2,51,09,754 मतदाता हैं। इसमें 93,021 डाउटफुल वोटर (D-वोटर) शामिल हैं। D-वोटर वे लोग होते हैं जिनकी नागरिकता पर संदेह है और उन्हें वोट देने की अनुमति नहीं होती। इन्हें फॉरेनर्स एक्ट, 1946 के तहत विशेष ट्रिब्यूनल द्वारा तय किया जाता है और इनके वोटर कार्ड अलग से जारी नहीं किए जाते। इस बार ड्राफ्ट रोल में D-वोटरों की जानकारी अलग से दर्ज की गई है।

चुनाव आयोग ने बताया कि इस स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया का कार्य 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक चला। इस दौरान 61 लाख से अधिक घरों का दौरा किया गया और हर मतदाता के विवरण की जांच की गई। इस काम में हजारों चुनाव अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर और सुपरवाइजर शामिल थे। इसके अलावा, राजनीतिक दलों ने निगरानी के लिए कुल 61,533 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए, ताकि वेरिफिकेशन पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो।

इस प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाने का मुख्य कारण मृत्यु, नई जगह पर शिफ्ट होना या डुप्लीकेट एंट्री होना बताया गया है। कुल 10.56 लाख नाम हटाए गए हैं, जिससे मतदाता सूची में वास्तविक और सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे। यह कदम विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अहम माना जा रहा है।

चुनाव आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट रोल 22 जनवरी तक मतदाताओं के दावे और आपत्तियों के लिए खुला रहेगा। इस अवधि में कोई भी मतदाता अपनी जानकारी में त्रुटि होने पर दावा या आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके बाद 10 फरवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित किया जाएगा, जो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अंतिम सूची के रूप में उपयोग किया जाएगा।

असम में इस प्रक्रिया से कुल 31,486 मतदान केंद्र तय किए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार के विशेष पुनरीक्षण से मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ी है और आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा आने की संभावना कम होगी। वहीं, राजनीतिक दलों के लिए भी यह चुनौतीपूर्ण कदम है, क्योंकि अब उन्हें वास्तविक मतदाताओं के आधार पर अपनी रणनीति बनानी होगी।

इस विशेष पुनरीक्षण की प्रक्रिया से यह भी स्पष्ट हो गया है कि राज्य में चुनाव आयोग ने तकनीकी और मानवीय संसाधनों का व्यापक उपयोग किया है। घर-घर जाकर सत्यापन, बूथ स्तर पर एजेंटों की तैनाती और डी-वोटरों का अलग से रिकॉर्ड रखना यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग ने चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाए हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के स्पेशल रिवीजन का परिणाम विधानसभा चुनाव के दौरान मतों की सटीक गिनती और निष्पक्ष परिणाम देने में सहायक होगा। इसके अलावा, मतदाता सूची से नाम कटने की प्रक्रिया राजनीतिक दलों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें वास्तविक वोटर बेस का आकलन करने में मदद करेगी।

इस प्रक्रिया को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में मतदाताओं और राजनीतिक दलों में जागरूकता बढ़ी है। यह साफ संकेत है कि असम में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी पक्ष निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सजग हैं। इस कदम को राज्य में लोकतंत्र की मजबूती और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

इस प्रकार, असम में 10.56 लाख वोटरों के नाम कटने के बाद राज्य की वोटर सूची अधिक सटीक और विश्वसनीय हो गई है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करती है और चुनाव आयोग की तत्परता और निष्पक्षता को दर्शाती है।

बोट्स्वाना के परिवहन मंत्री नूह सलाके ने बरेका का किया दौरा, रेल तकनीक की सराहना

(जीएनएस)। वाराणसी। शनिवार को बोट्स्वाना सरकार के परिवहन एवं अवसंरचना मंत्री नूह सलाके बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका) पहुंचे और यहां के आधुनिक रेल इंजन उत्पादन केंद्र का औपचारिक भ्रमण किया। मंत्री ने बरेका में निर्मित अत्याधुनिक लोकोमोटिव इंजनों की उत्पादन प्रक्रिया, तकनीकी विशेषताओं और गुणवत्ता मानकों का गहन अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (उत्पादन एवं विपणन) सुनील कुमार ने मंत्री को न्यू ब्लॉक शॉप, टर्बो शॉप, लाइट मशीन शॉप, सब-असेंबली शॉप, ईएस एवं ईटी शॉप, लोको असेंबली शॉप और लोको टेस्ट शॉप का निरीक्षण कराया। मंत्री ने प्रत्येक कार्यशाला में चल रही गतिविधियों और उत्पादन तकनीक की जानकारी ली तथा भारतीय रेल इंजनों में इस्तेमाल हो रही स्वदेशी तकनीक की तारीफ की।

इस अवसर पर बरेका के डिज़ाइन विभाग का भी दौरा किया गया। मंत्री ने विभिन्न लोकोमोटिव इंजनों के डिज़ाइन मॉडल और डिजाइन आधारित निर्माण प्रक्रिया को देखा। उन्होंने इस अवसर पर कारखाना में अपनाई जा रही नवाचारपूर्ण तकनीकों और डिज़ाइन प्रणाली की कार्यकुशलता की सराहना की। भ्रमण के बाद प्रशासन भवन में आयोजित बैठक में महाप्रबंधक सभा कक्ष में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बरेका की उत्पादन क्षमता, निर्यात गतिविधियों और स्वदेशी तकनीक पर आधारित लोकोमोटिव निर्माण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर सुशील कुमार श्रीवास्तव ने रेल इंजनों की तकनीकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला और उनके संचालन, दक्षता एवं ऊर्जा बचत क्षमता पर मंत्री को अवगत कराया।

बैठक के अंत में मंत्री नूह सलाके को बरेका प्रशासन की ओर से स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजीनियर विवेक शील, मुख्य अभिकल्प इंजीनियर (डीजल) प्रवीण कुमार तथा बरेका एवं राइट्स के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री नूह सलाके ने कहा कि बरेका की उत्पादन प्रणाली अत्याधुनिक है और भारत में रेल इंजन निर्माण की तकनीक अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। उन्होंने कहा कि बोट्स्वाना भी भारतीय तकनीक से लाभ उठाकर अपने देश में रेल इंजन उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहयोग करेगा। बरेका के इस दौरे ने दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग और ज्ञान आदान-प्रदान की संभावनाओं को और मजबूत किया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि बरेका में इस्तेमाल हो रही स्वदेशी तकनीक और उत्पादन प्रणाली भारतीय रेल इंजन निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। मंत्री का यह दौरा न केवल भारत के रेल इंजन उद्योग की वैश्विक पहचान को बढ़ाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निर्यात संभावनाओं को भी नई दिशा प्रदान करता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 2025 में दिलवाए 45 करोड़ रुपये का रिफंड, 67 हजार से अधिक शिकायतें सुलझाईं

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) ने वर्ष 2025 में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। हेल्पलाइन के माध्यम से देशभर के उपभोक्ताओं को कुल 45 करोड़ रुपये का रिफंड दिलाया गया, जबकि 67,265 से अधिक शिकायतों का समयबद्ध और मुकदमे से पहले निस्तारण किया गया। यह पहल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत मुकदमों से पहले समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि 25 अप्रैल से 26 दिसंबर 2025 के बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 31 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया। इस दौरान उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत प्रदान करने के साथ ही उपभोक्ता आयोगों पर दबाव कम किया गया। सबसे अधिक शिकायतें ई-कॉमर्स सेक्टर से आईं, जहां लगभग 40 हजार मामलों में 32 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड कराया गया। इसके बाद यात्रा और पर्यटन क्षेत्र रहा, जिसमें 3.5 करोड़ रुपये की वापसी सुनिश्चित हुई।

मंत्रालय ने कुछ वास्तविक उदाहरण साझा किए। जोधपुर के रमेश कुमार (नाम परिवर्तित) ने ऑनलाइन मंगाई गई कुर्सियों की शिकायत की, जो खराब हालत में आई थीं। कंपनी के बार-बार असफल प्रयासों के बावजूद, एनसीएच के हस्तक्षेप से उन्हें कुछ ही दिनों में पूरा रिफंड मिला। इसी तरह बेंगलुरु के एक उपभोक्ता ने इंटरनेट प्लान का भुगतान किया, लेकिन कनेक्शन नहीं मिला। चार महीने तक भटकने के बाद एनसीएच की मदद से तत्काल धन वापसी हुई। चेन्नई में फ्लाइट टिकट रिफंड से जुड़े एक मामले में भी हेल्पलाइन के हस्तक्षेप से उपभोक्ता को राहत मिली।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन अब उपभोक्ताओं के लिए मुकदमे से पहले शिकायत निवारण का सिंगल पॉइंट एक्सेस बन चुकी है। नागरिक टोल-फ्री नंबर 1915 पर 17 भाषाओं में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा INGRAM पोर्टल, व्हाट्सऐप (8800001915), एसएमएस, ईमेल, एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल और उमंग ऐप के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है।

मंत्रालय ने देशभर के उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का अधिक से अधिक उपयोग करें और समय पर न्याय पाएं। एनसीएच की यह उपलब्धि डिजिटल युग में उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है और इससे उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी और वित्तीय सुरक्षा मिल रही है।

राजकोट जिले के लूनीवाव प्राइमरी स्कूल में राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने रात्रि विश्राम कर दी सादगी भरे जीवन का संदेश

(जीएनएस)। राजकोट। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी ने गोंडल तालुका के लूनीवाव गांव का दौरा करते हुए सादगी और साधारण जीवन की महत्ता पर जोर दिया। राज्यपाल ने गांव के प्राथमिक स्कूल के कॉमन रूम में रात्रि विश्राम किया और इस अवसर पर ग्रामीण जीवन की सरलता को अपनाने तथा सादगीपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया।

राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी का यह दौरा ग्रामीण समुदायों और सरकारी स्कूलों के साथ उनकी निकटता और जुड़ाव को दर्शाता है। अपने पिछले भ्रमणों के अनुभवों के अनुसार, राज्यपाल हमेशा साधारण सरकारी भवनों, स्कूलों और पंचायत भवनों में ठहरकर समाज के लिए प्रेरक संदेश देते हैं कि भौतिक सुविधाओं की अधिकता में ही सुख नहीं है, बल्कि सादगी और अनुशासनपूर्ण जीवन से आत्मिक संतोष प्राप्त होता है।

लूनीवाव प्राइमरी स्कूल में रात्रि विश्राम के बाद राज्यपाल ने सुबह-सुबह स्कूल परिसर में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। इस योग अभ्यास में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। योग सत्र की शुरुआत राज्यपाल द्वारा बच्चों को सूक्ष्म व्यायाम और शारीरिक प्रशिक्षण के महत्व की जानकारी देने से हुई। इसके बाद उन्होंने भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम और विभिन्न प्राणायाम तकनीकों के माध्यम से बच्चों को श्वसन और मानसिक संतुलन के लाभों से परिचित कराया। योग सत्र के अंत में सभी ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया, जिससे बच्चों में अनुशासन, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की भावना विकसित हुई।

राज्यपाल ने इस अवसर पर बच्चों को शिक्षा, संस्कृति और स्वच्छता के महत्व पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि लूनीवाव प्राइमरी स्कूल में नियमित रूप से योग शिक्षा दी जा रही है और इसके लिए शिक्षकों की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल पुस्तक ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भी समुचित शिक्षा शामिल होनी चाहिए।

अपने भाषण में आचार्य देवव्रतजी ने बच्चों और ग्रामीणों को सादगीपूर्ण जीवन के महत्व पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक भौतिक सुख और सुविधाओं के पीछे भागने से जीवन की मूल सार्थकता खो जाती है। सरल जीवन जीकर हम न केवल अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी प्रसारित कर सकते हैं।

राज्यपाल का यह दौरा स्थानीय लोगों के लिए भी प्रेरणास्रोत रहा। ग्रामीणों ने कहा कि राज्यपाल की यह पहल बच्चों और युवाओं में अनुशासन, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी। इसके साथ ही ग्रामीण समुदाय में शिक्षा के महत्व के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा।

आचार्य देवव्रतजी ने बताया कि उनका उद्देश्य केवल सरकारी भवनों या स्कूलों का निरीक्षण करना नहीं है, बल्कि बच्चों, शिक्षकों और ग्रामीणों के बीच जाकर उन्हें प्रेरित करना और जीवन में अनुशासन, स्वास्थ्य और सादगी के मूल्यों को अपनाने के लिए संदेश देना है। उन्होंने कहा कि सादगी और योग के माध्यम से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों मजबूत होता है और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है।

इस कार्यक्रम में शिक्षक, स्कूल प्रशासन और स्थानीय समाजसेवी भी उपस्थित रहे। उन्होंने राज्यपाल की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे दौरे बच्चों के लिए सीधे प्रेरक होते हैं और उन्हें जीवन में अनुशासन, स्वास्थ्य और सकारात्मक आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

इस अवसर पर राज्यपाल ने यह भी आश्वासन दिया कि वह भविष्य में समय-समय पर ऐसे गांवों और स्कूलों का दौरा करते रहेंगे, ताकि बच्चों और युवाओं में शिक्षा, योग और सादगीपूर्ण जीवन की समझ और जागरूकता बढ़ती रहे।

राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी का यह सादगीपूर्ण व्यवहार और ग्रामीण जीवन के प्रति सम्मान लोगों के बीच एक मिसाल बन गया। उनका यह संदेश स्पष्ट करता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ सरल जीवन शैली को अपनाना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस प्रकार, लूनीवाव प्राइमरी स्कूल में राज्यपाल का रात्रि विश्राम और योग सत्र न केवल बच्चों के लिए बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए एक प्रेरक उदाहरण बन गया, जिसने सादगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति के मूल्यों को एक साथ प्रस्तुत किया।

सूरत में मारवाड़ी युवा मंच और जागृति शाखा द्वारा ग्रामीण कन्याओं के लिए भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित

(जीएनएस)। सूरत। मारवाड़ी युवा मंच एवं उसकी जागृति शाखा, सूरत ने शनिवार, 27 दिसंबर को ग्रामीण कन्याओं के लिए एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। यह कार्यक्रम वेसु स्थित श्री देवसर माता मंदिर के हॉल में सम्पन्न हुआ, जो श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के निकट स्थित है। समारोह का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की कन्याओं को वैदिक परंपरा के अनुसार विवाह सम्पन्न कराने में मदद करना था।

जागृति शाखा की अध्यक्ष स्वाति चौधरी ने बताया कि इस आयोजन में कुल सात जोड़ों का विवाह पूर्ण वैदिक विधि-विधान के अनुसार संपन्न कराया गया। सूरत शाखा के अध्यक्ष गणेश अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 8 बजे हुई और सुबह 10 बजे सभी जोड़ों की बारात निकाली गई। इसके बाद परंपरागत वरमाला एवं फेरे की रस्में सम्पन्न हुईं, जिसमें वर-वधुओं ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह बंधन में बंधे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जे. पी. अग्रवाल (रचना ग्रुप) ने नवविवाहित वर-वधुओं को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर गुजरात प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष अजय अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री प्रकाश बिंदल, सूरत जागृति शाखा की संस्थापक प्रेरणा भाऊवाला और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से सुषमा जी अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

उनका मानना था कि इस प्रकार के सामूहिक विवाह कार्यक्रम सामाजिक समरसता और सेवा भावना को बढ़ावा देते हैं।

कार्यक्रम में सूरत जागृति शाखा की इंदु खेराड़ी, कुसुम अग्रवाल, सभी पूर्व अध्यक्ष, कार्यक्रम संयोजक सुनीता खेतान, सुनीता सरावगी, शालिनी चाचान और मेहा मोदी सहित पूरी कार्यकारिणी सक्रिय रूप से मौजूद रही। वहीं सूरत शाखा की ओर से अमित केडिया, अभिषेक, प्रभात जालान, सिद्धार्थ, राजेश और सुशांत बजाज सहित सभी पदाधिकारी एवं सदस्य कार्यक्रम में शामिल होकर उसे सफल बनाने में योगदान दिया।

समारोह में सामाजिक समरसता, सेवा भावना और सामूहिक सहभागिता की स्पष्ट झलक देखने को मिली। यह आयोजन न केवल नवविवाहित जोड़ों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी यादगार बन गया। उपस्थितजनों ने इस पहल की सराहना की और इसे ग्रामीण समाज में समान अवसर और सामाजिक न्याय के प्रतीक के रूप में देखा।

स्वाति चौधरी और गणेश अग्रवाल ने बताया कि मारवाड़ी युवा मंच एवं जागृति शाखा का यह प्रयास लगातार ग्रामीण कन्याओं और उनके परिवारों के लिए सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सामूहिक विवाह समारोह समाज में भाईचारे और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देते हैं और लोगों को परंपराओं के अनुसार जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं।

कार्यक्रम में वर-वधुओं और उनके परिवारों के चेहरे पर प्रसन्नता और उत्साह साफ देखा जा सकता था। आयोजकों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी विवाह विधिपूर्वक और पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हों। समारोह के दौरान उपस्थित वरिष्ठ समाजसेवकों और व्यापारियों ने नवविवाहित जोड़ों के उज्जवल भविष्य और खुशहाल जीवन की कामना की।

समारोह में उपस्थित लोग, चाहे वे समाजसेवी हों या व्यापारी, सभी ने इस पहल को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे सामूहिक विवाह कार्यक्रम समाज में एकजुटता और सहयोग की भावना को मजबूत करते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए भी बड़े अवसर पैदा करते हैं।

इस भव्य आयोजन का उद्देश्य केवल विवाह कराना नहीं था, बल्कि यह ग्रामीण समाज में सामाजिक चेतना, सेवा और सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देने वाला था। मारवाड़ी युवा मंच और जागृति शाखा का यह प्रयास समाज के लिए मिसाल कायम करता है कि कैसे सामूहिक प्रयास और सहयोग से ग्रामीण समुदाय के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

इस प्रकार, सूरत में आयोजित यह सामूहिक विवाह समारोह न केवल सात जोड़ों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणास्रोत बन गया, जिसने सामाजिक समरसता, परंपरा, सेवा और सहयोग के मूल्य को उजागर किया।